

सेवाएं

कोविड-19 महामारी के बाद किए गए लॉक डाउन तथा सामाजिक दूरी के उपायों का संपर्क गहन सेवा क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में सेवा क्षेत्र लगभग 16% तक संकुचित हो गया। मार्च 2020 में पहली बार लॉक-डाउन की घोषणा होते ही हवाई यात्री यातायात, रेल माल यातायात, बंदरगाह यातायात, विदेशी पर्यटकों के आवागमन, तथा विदेशी मुद्रा से होने वाली आय में बहुत तेज गिरावट देखी गई। अनलॉक चरण के बाद अर्थव्यवस्था के धीरे-धीरे पटरी पर आने से इनमें से अधिकांश संकेतकों में सुधार होता दिख रहा है। ‘सेवा क्रय प्रबंधन’ सूचकांक, रेल माल यातायात तथा बंदरगाह यातायात में आ रही गिरावट अब थम गई है और इनमें धीरे-धीरे होती वृद्धि V-आकार में सुधार दर्शा रही है। घरेलू हवाई यात्री यातायात में भी धीरे-धीरे मासिक आधार पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में यात्रा मंद है। इसके अलावा वैश्विक पटल पर उभरी बाधाओं के बावजूद सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) अंतर्वाह काफी मजबूत हुआ है तथा पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल-सितम्बर 2020 में हुई वर्ष दर वर्ष 34 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 23.61 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। वर्ष 2020-21 में कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार हुए। अंतरिक्ष क्षेत्र खोल दिया गया था आई-टी-बीपीओ क्षेत्र से दूरसंचार संबंधी विनियमन हटा दिए गए थे, और ई-कॉमर्स के लिए उपभोक्ता संरक्षण नियमों की पेश किया गया था।

भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का महत्व बरकरार है, इस समय समग्र अर्थव्यवस्था तक सकल संवर्द्धन मूल्यवर्धन (जीवीए) में इसका हिस्सा 54% से अधिक है तो भारत में आने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में चार बटे पांचवा हिस्सा 54% है। तथापि वर्ष 2010-11 में बंदरगाहों पर (शिपिंग टर्नअराऊंड टाइम) 4.67 दिन था जो वर्ष 2019-20 में घटकर 2.62 दिन लगभग आधा रह गया है। भारत 38 यूनीकॉर्न (स्टार्ट-अप) का घर है तथा उल्लेखनीय है कि इनमें से रिकार्ड 12 स्टार्ट-अप पिछले वर्ष ही यूनीकॉर्न सूची में जुड़े हैं।

भारत में सेवा क्षेत्र का निष्पादन-सिंहावलोकन

9.1 सेवा क्षेत्र पर कोविड-19 का असर कोविड-19 महामारी और उसके कारण देशभर में तथा विश्वभर में मार्च 2020 से लगाए गए लॉक डाउन ने वर्ष 2020 को एक असामान्य वर्ष बना डाला। संपर्क-गहन सेवा क्षेत्र विशेषकर पर्यटन, उड्डयन एवं आतिथ्य जैसे उप-क्षेत्र इससे बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के पूर्वांक में सेवा क्षेत्र लगभग 16% वर्ष दर वर्ष तक संकुचित हो गया (तालिका 1) जिसका कारण सभी उप-क्षेत्रों विशेषकर ‘व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण संबंधित सेवाओं में तेजी से आई गिरावट थी जो पूर्वांक वित्त-वर्ष 2020-21 में 31.5 प्रतिशत दर्ज की गई। प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन में 2020-21 में 8.8 प्रतिशत तक संकुचन का अनुमान लगाया गया है जबकि 2019-20 (तालिका-1) में इनमें 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। उप-क्षेत्र ‘व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं’, ‘वित्तीय,

रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं', तथा लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं' में क्रमशः 21.41 प्रतिशत, 3.68 प्रतिशत तथा 0.82 प्रतिशत का संकुचन होने का अनुमान है। यह उल्लेखनीय है कि जहां वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही (Q1) में 20 प्रतिशत से अधिक का संकुचन हुआ वही दूसरी तिमाही (Q2) यह कम होकर 11.4% हो गया। अनुमान से तेज गति से हुआ यह सुधार मौटे तौर पर उच्च आवृत्ति संकेतकों की पुष्टि करता है तो जून 2020 में अर्थव्यवस्था को नियंत्रित तरीके से खोले जाने के बाद अर्थव्यवस्था की गति में आई तेजी से इंगित करते हैं।

तालिका 1: भारत के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का निष्पादन

क्षेत्र	सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा		वर्ष दर वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)				
	2020-21 (AE)	2018-19 (1st RE)	2019-20 (PE)	2020-21 (AE)	2020-21 (H1)	2020-21 Q1	2020-21 Q2
कुल सेवाएं (निर्माण कार्य के अलावा)	54.3	7.7	5.5	-8.8	-15.9	-20.6	-11.4
व्यापार, होटल पविहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं	15.4	7.7	3.6	-21.41	-31.5	-47.0	-15.6
वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	22.2	6.8	4.6	-0.82	-6.8	-5.3	-8.1
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	16.7	9.4	10.0	-3.68	-11.3	-10.3	-12.2

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

टिप्पणी: हिस्सा वर्तमान मूल्य पर है और वृद्धि-स्थिर 2011-12 मूल्य पर है; आई संशोधित अनुमान; पीई अनंतिम अनुमान; एई अग्रिम अनुमान

9.2 भारत की सेवा क्षेत्र गतिविधि जो मांग पर कोविड-19 महामारी के आघात के कारण मार्च माह से लगातार पांच माह तक मंद पड़ी रही, सितम्बर 2020 से स्फूर्ति में आई है। IHS मार्किट इंडिया सर्विस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स, जिसे सेवा क्रय प्रबंधन सूचकांक (पीएमआई) के तौर पर भी जाना जाता है, फरवरी 2020 में 57.5 था जो 85 महीनों के उच्च स्तर पर था लेकिन अप्रैल 2020 (चित्र 1(क)) में 5.4 के निम्नतम स्तर पर लुढ़क गया था। गतिशीलता पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिए जाने तथा कारोबार फिर से शुरू होने पर सेवा पी एम आई में तेजी से सुधार हुआ और अक्टूबर 2020 तक यह बढ़कर 54.1 हो गया। हालांकि दिसम्बर 2020 में सूचकांक में नरमी आई, यद्यपि 50 के ऊपर मुद्रण का अर्थ वृद्धि से संबंधित है।

9.3 इसी प्रकार रेल माल यातायात वृद्धि सितम्बर 202 में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 15.5 प्रतिशत की तीव्र गति पकड़ने से पहले अप्रैल 2020 में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में (-)35.3 प्रतिशत वर्ष दर वर्ष तक कम हो गई थी (चित्र 1(ख)) वृद्धि में यह गति दिसम्बर 2020 तक बनी रही है। भारतीय रेलवे माल लदाई दिसम्बर 2020 में 118.13 मिलियन टन थी जो पिछले वर्ष समान अवधि में की गई माल लदाई (108.84 मिलियन टन) की तुलना में 8.54 प्रतिशत अधिक है। उल्लेखनीय है कि रेलवे में माल यातायात को बहुत आर्कषक बनाने के लिए भारतीय रेलवे में विभिन्न रियायतें/छूट प्रदान की जा रही हैं।

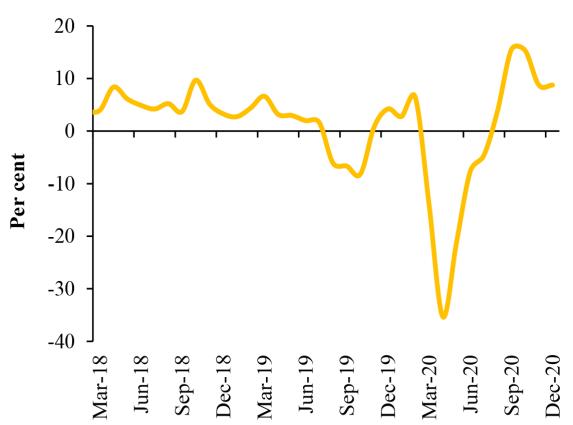
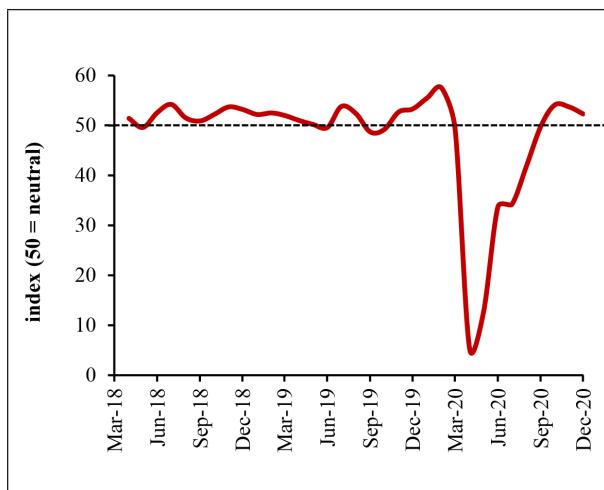
9.4 मार्च और मई के बीच लगभग दो माह तक इंडियन एयरलाइन्स पूर्णतः अवरुद्ध रही क्योंकि सरकार ने महामारी को फैलने से रोक के लिए यात्राओं को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था। परिणाम स्वरूप अप्रैल 2020 में हवाई यात्री यातायात में बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिली (चित्र 1 (ग))। एयरलाइन्स को मई माह में नियंत्रित तरीके से घरेलू प्रचालन आरंभ करने की अनुमति दे दी गई। घरेलू हवाई यात्री यातायात में अगस्त

माह से मासिक आधार पर धीरे-धीरे सुधार होता दिख रहा है हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में यात्रा मांग मंद बनी हुई है। महानिदेशक, नागरिक विमानन (डी जी सी ए) के अनुसार नवम्बर माह तक 63.54 लाख घरेलू यात्रियों ने हवाई यात्रा की थी जो अक्टूबर माह में हवाई यात्रा करने वाले 52.71 लाख यात्रियों से 20.54 प्रतिशत अधिक थे। हालांकि नवम्बर 2020 में घरेलू वायु यातायात नवम्बर 2019 की तुलना में 50.93 प्रतिशत कम रहा। नवम्बर 2019 में 1.3 करोड़ यात्रियों ने हवाई यात्रा की थी।

9.5 सितम्बर 2018 और दिसम्बर 2019 के बीच सेवा क्षेत्र में बैंक ऋण वृद्धि में काफी मजबूती आई हालांकि एक वर्ष पहले के 4.84 प्रतिशत की तुलना में नवम्बर 2020 की समाप्ति पर वर्ष दर वर्ष 8.76 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इन सेवा क्षेत्रों की क्रेडिट वृद्धि में 2020 में मजबूती आई थी (चित्र 1(घ))। इसे पर्यटन, होटल और रेस्त्रां, 'परिवहन परिचालकों' और 'अन्य सेवाओं' मापक उपक्षेत्रों में वृद्धि द्वारा इसे परिचालित किया गया था। हालांकि "पेशेवर सेवाओं" और "नौपरिवहन" की बैंक क्रेडिट की वृद्धि में क्रमशः 24.66 प्रतिशत और 20.51 प्रतिशत तक वर्ष दर वर्ष संकुचन आया (तालिका 2)।

चित्र 1(क): सेवाओं का पीएमआई सूचकांक

चित्र 1(ख) रेल माल यातायात में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)



स्रोत: एचआइएस मार्किट इकोनॉमिक्स, नागर विमानन महानिदेशालय

चित्र 1(ग): हवाई यात्री यातायात में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

चित्र 1(घ): सेवा क्षेत्र में बैंक ऋण में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रेलवे

तालिका 2: सेवा उप-क्षेत्रों में बैंक ऋण में वृद्धि

	नवम्बर 2020	नवम्बर 2019
सेवाएं	8.76	4.84
ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर	10.73	8.14
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	0.36	-0.39
पर्यटन, होटल और रेस्टॉरंट	18.04	13.09
जहाजरानी	-20.51	5.13
पेशेवर सेवाएं	-24.66	1.30
वाणिज्यिक अचल संपदा	5.69	6.04
एन बी एफ सी	5.65	17.60
खुदरा व्यापार	7.84	29.06
थोक व्यापार (खाद्य अधिप्राप्ति को छोड़कर)	15.81	-19.53
अन्य सेवाएं	-3.5	11.3

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर सेवा क्षेत्र का हिस्सा

9.6 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 15 में सकल राज्य मूल्य संबद्धन (जीएसवीए) में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 50 प्रतिशत से ज्यादा है (तालिका 3)। 8 राज्यों में सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य संबद्धन में योगदान 60 प्रतिशत से अधिक है। चंडीगढ़ और दिल्ली में यह हिस्सेदारी 85 प्रतिशत से अधिक है। जबकि सिकिम का हिस्सा 27.02 प्रतिशत से सबसे कम बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि सकल राज्य मूल्य संबद्धन में सेवाओं की अपेक्षाकृत कम हिस्सेदारी वाले राज्यों जैसे त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, आंध्रप्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश झारखण्ड, ओडिशा तथा अरुणाचल प्रदेश में भी हाल के वर्षों में सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई है।

तालिका 3: राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन

राज्य	2019-20 में सकल मूल्य संबद्धन में सेवा क्षेत्र में 5 वर्षों की औसत वृद्धि (प्रतिशत की हिस्सेदारी (प्रतिशत में) में, वर्ष-दर-वर्ष)
चंडीगढ़*	88.29
दिल्ली	85.16
अंडमान और निकोबार*	68.12
कर्नाटक	66.19
तेलंगाना	65.19
केरल*	63.73
मणिपुर*	62.64
जम्मू और कश्मीर*	60.08
महाराष्ट्र*	59.75
बिहार	59.45
मेघालय	58.48
नागालैंड*	56.39

राज्य	2019-20 में सकल मूल्य संवर्द्धन में सेवा क्षेत्र में 5 वर्षों की औसत वृद्धि (प्रतिशत में, वर्ष-दर-वर्ष)
पश्चिम बंगाल	55.97 6.94
तमिलनाडु	53.67 6.29
हरियाणा	50.44 8.98
पुडुचेरी	49.67 6.22
उत्तर प्रदेश*	48.95 7.05
मिजोरम*	47.60 7.09
पंजाब	46.71 6.90
त्रिपुरा	46.71 10.50
राजस्थान	46.63 7.51
असम*	46.57 5.68
झारखण्ड	45.28 7.69
हिमाचल प्रदेश	43.88 7.01
अरुणाचल प्रदेश*	43.23 8.22
उत्तराखण्ड	43.23 9.47
आंध्रप्रदेश	41.80 7.56
ओडिशा	40.84 7.20
गोवा*	38.53 6.01
छत्तीसगढ़	36.86 7.02
मध्यप्रदेश	36.77 8.01
गुजरात*	35.62 8.66
सिक्किम	27.02 6.22

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

टिप्पणी: *2018-19 के आंकड़ों के आधार पर; **2015-16 से 2019-20 तक का औसत, या जहाँ 2019-20 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहाँ 2014-15 से 2018-19 तक का औसत।

सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई)

9.7 व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू.एन सी टी ए डी) द्वारा जारी की गई नवीनतम वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के सबसे बड़े एफ डी आई प्राप्तकर्ताओं की सूची में भारत का स्थान वर्ष 2019 सुधर कर 9वाँ हो गया जो 2018 में 12वाँ था। अप्रैल-सितम्बर 2020 के दौरान वैश्विक मंदी, कोविड-19 महामारी, लॉकडाउन से जुड़े उपायों तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं के अवरुद्ध होने के बावजूद भारत में एफ डी आई में पिछली वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 17 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई। सेवा क्षेत्र¹ में, जो भारत में एफ डी आई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, अप्रैल-सितम्बर 2020 के दौरान मजबूत वृद्धि देखने को मिली। सेवा क्षेत्र में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाहों (पुनः निवेशित आय को छोड़कर) में अप्रैल-सितम्बर 2020 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप

1. वित्तीय सेवाओं, कारोबारी सेवाओं, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी परीक्षण एवं विश्लेषण, कूरियर, दूरसंचार, व्यापार, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, होटल एवं पर्यटन, अस्पताल एवं निदान केंद्र, परगमर्श सेवाएं, समुद्री परिवहन, सूचना एवं प्रसारण, खुदरा व्यापार, कृषि सेवाएं, शिक्षा तथा हवाई परिवहन में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह के रूप में अनुमानित हैं।

यह 23.61 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह इस अवधि में भारत में कुल सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह का लगभग चार बटा पांचवां हिस्सा है। (तालिका 4)। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह में इस उछाल का कारण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर' उपक्षेत्र में मजबूत अंतर्वाह होना था जहां एफ डी आई अंतर्वाह बढ़कर 17.55 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 336 प्रतिशत से भी अधिक है। 'खुदरा व्यापार', 'कृषि सेवाओं' तथा 'शिक्षा' जैसे उप-क्षेत्रों में भी एफ डी आई अंतर्वाह में उच्च वृद्धि दर्ज की गई।

तालिका 4: सेवा क्षेत्र में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह

सेवा उप क्षेत्र	2019-20 में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह में हिस्सेदारी**	सकल प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी अंतर्वाह (मिलियन अमेरिकी डॉलर)			
		2018-19	2019-20	अप्रैल-सितं 2019	अप्रैल-सितं 2020
वित्त, व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कूरियर, तकनीकी जांच एवं विश्लेषण	9.54	9,158	7,854	4,455	2,252
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर	74.34	6,415	7,673	4,025	17,554
व्यापार (आंकड़े मूल से देखे)	4.02	4,462	4,574	2,143	949
दूरसंचार	0.03	2,668	4,445	4,280	7
सूचना एवं प्रसारण	0.68	1,252	823	196	161
होटल एवं पर्यटन	1.20	1,076	2,938	859	283
अस्पताल एवं निदान केंद्र	0.69	1,045	635	376	163
शिक्षा	2.56	777	3,245	216	604
खुदरा व्यापार	5.21	443	472	243	1,230
परामर्श सेवाएं	0.46	411	1,047	473	110
समुद्री परिवहन	0.61	279	199	173	144
हवाई परिवहन	0.41	191	918	114	97
कृषि सेवाएं	0.25	88	46	23	60
सेवा क्षेत्र में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी अंतर्वाह (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)		28,265	34,868	17,577	23,612
पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (प्रतिशत वर्ष-दर वर्ष)		-2.4	23.4	33.1	34.3
भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)		44,366	49,977	26,096	30,004
सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)		63.7	69.8	67.4	78.7

स्रोत: उद्योग एवं आंतरिक संवर्धन विभाग (डी वी आई आई टी)

टिप्पणी: *पुनः निवेशित आय को छोड़कर।

सेवा क्षेत्र में व्यापार

9.8 वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी ने सेवाओं संबंधी वैश्विक व्यापार पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डाला उसके परिणाम स्वरूप विश्वभर में आपूर्ति शृंखलाएं भंग हो गई। जहां विश्व व्यापार संगठन ने वर्ष 2020 में वैश्विक वाणिज्य-वस्तु व्यापार वृद्धि में 9.2 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान लगाया है वहीं आई एम एफ ने वैश्विक माल एवं सेवा व्यापार में वर्ष 2020 में 10.4 प्रतिशत तक संकुचन होने की आशंका जताई हैं विश्व व्यापार संगठन सेवा व्यापार गतिविधि सूचकांक ने वाणिज्यिक सेवाओं में विश्व व्यापार में 2020 के पहले तीन महीनों में 4.3 प्रतिशत की कमी आने का संकेत देकर कोविड-19 के प्रसार के प्रतिकूल प्रभावों को आंशिक रूप से दर्शाया था। 2020 की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान वर्ष-दर-वर्ष 30 प्रतिशत की तेज गिरावट दर्ज की गई क्योंकि कई देशों ने लॉकडाउन तथा परिवहन संबंधी प्रतिबंध लगा दिए थे जिनमें सीमा-पार (क्रॉस बॉर्डर) उपाय भी शामिल थे।

9.9 सेवा क्षेत्र निर्यात में भारत की पकड़ बहुत मजबूत है। वर्ष 2019 में यह वाणिज्यिक सेवा में दस शीर्ष देशों में शामिल था तथा विश्व सेवा निर्यात क्षेत्र में इसकी भागीदारी 3.5% थी।

महामारी से हुए नुकसान के बावजूद के माल व्यापार की तुलना में भारत सेवा क्षेत्र में अपेक्षाकृत लचीलापन बना रहा। कुछ उप-क्षेत्रों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बावजूद इस क्षेत्र से वर्तमान आय का प्रवाह स्थिर बना रहा। वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में निवल सेवा निर्यात आय पिछले वर्ष के 40.47 बिलियन यू.एस. डॉलर की तुलना में 41.67 यू.एस. डॉलर थी।

9.10 भारत के सेवा निर्यात में वर्ष 2019-20 वर्ष 2018-19 के 6.6 प्रतिशत की तुलना में 2.5 प्रतिशत की नरमी दर्ज की गई क्योंकि मुख्यतः परिवहन, बीमा तथा संचार सेवाओं से होने वाली आय में कमी आई। वैश्विक मांग में गिरावट तथा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन संबंधी उपाय किए जाने के चलते वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में पिछले वर्ष की समान अवधि में हुई 6.39 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 7.87 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई (तालिका 5)।

तालिका 5: उप-क्षेत्रवार सेवा व्यापार प्रदर्शन

वस्तु समूह	हिस्सा (प्रतिशत में)		मूल्य (अरब अमेरिकी डॉलर में)		वृद्धि (प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष)			
	2009-10	2019-20	2018-19	2019-20	2020-21 (अप्रैल-जून)	2018-19	2019-20	2020-21 (अप्रैल-जून)
कुल सेवा निर्यात	100	100	208.00	213.19	96.71	6.60	2.50	-7.87
यात्रा	12.3	14.10	28.44	30.00	3.87	0.30	5.50	-73.49
परिवहन	11.6	9.80	19.46	20.99	10.28	11.60	7.80	-2.34
बीमा	1.7	1.10	2.66	2.43	1.15	6.20	-8.70	-2.99
जी एन आई ई*	0.5	0.30	0.61	0.66	0.29	-8.10	8.00	-8.81
सॉर्टवेयर सेवाएं	51.8	43.70	83.47	93.10	47.69	7.90	11.50	3.55
कारोबारी सेवाएं	11.8	18.80	39.11	45.72	22.91	4.70	16.90	2.48
वित्तीय सेवाएं	3.8	2.30	4.86	4.73	2.01	-5.90	-2.60	-20.35
संचार	1.3	1.20	2.56	2.72	1.37	22.10	6.30	2.44
कुल आयात सेवा	100	100.00	126.06	128.27	55.04	7.30	1.80	-13.95

यात्रा	15.6	17.20	21.70	22.01	5.49	11.20	1.40	- 55.09
परिवहन	19.9	18.90	20.53	24.28	8.98	16.60	18.30	- 25.90
बीमा	2.1	1.40	1.79	1.74	0.92	5.30	-2.90	19.44
जी एन आई ई*	0.9	0.90	1.11	1.11	0.52	40.30	-0.70	- 13.95
सॉफ्टवेयर सेवाएं	2.4	6.60	5.81	8.46	4.62	13.10	45.50	15.60
कारोबारी सेवा	30.1	36.50	40.41	46.88	23.69	10.30	16.00	4.22
वित्तीय सेवा	7.7	2.30	3.49	2.92	2.17	-37.00	-16.30	94.80
संचार	2.3	1.00	1.13	1.30	0.66	18.40	14.70	3.24
सेवा व्यापार शेष			81.94	84.92	41.67			
माल व्यापार शेष		-180.28	-157.51	- 25.55				

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त डाटा के आधार पर परिकलित

टिप्पणी: जी एन आई ई-सरकार को अन्यत्र शामिल नहीं है वृद्धि दर अमेरिकी डॉलर में दर्ज मूल्यों पर आधारित है।

9.11 विश्वभर में आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंधों की बजह से विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आने के कारण 2020-21 की प्रथम तिमाही में यात्रा से आय में 73.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई जिसमें पिछले वर्ष समान अवधि के दौरान 8.21 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई थी। व्यापार गतिविधि में मंदी आने तथा आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम छमाही परिवहन से होने वाली आय 2.34 प्रतिशत घट गई जबकि वित्त वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में इसमें 10.77 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि सॉफ्टवेयर निर्यात, जिसकी कुल सेवा निर्यात में 49.3% हिस्सेदारी है, महामारी से उत्पन्न नई चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजिटल सहायता, क्लाउड सेवाओं तथा अवसंरचना के आधुनिकीकरण की उच्च मांग के कारण इस कठिन परिस्थिति से उबरने में सक्षम रहा। वास्तव में अधिकांश सॉफ्टवेयर कंपनियों ने, जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में ऋणात्मक राजस्व वृद्धि होने की रिपोर्ट दी थी, दूसरी तिमाही में वृद्धि होने की रिपोर्ट दी थी, सकारात्मक तेजी आने के संकेत दिए हैं क्योंकि उनकी वित्तीय, बैंकिंग एवं बीमा, खुदरा, जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल यूनिटों से प्राप्त होने वाले राजस्व में बढ़ोतरी हुई है।

9.12 जैसा कि गार्टनर का अनुमान था (अक्टूबर 2020), हालांकि वर्ष 2020 में वैश्विक आई टी खर्च में 5.4 प्रतिशत की कमी संभावित है पर वर्ष 2021 में चरणबद्ध सुधारों की शुरूआत के बाद इसमें उछाल आएगा। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में, व्यवसाय सेवा निर्यात में 2020-21 के पहली छमाही में 2.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

9.13 वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम छमाही में सेवा निर्यातों की तुलना में सेवा आयातों में 13.95 प्रतिशत की तेज गिरावट देखी गई। सभी प्रमुख सेवाओं के आयात के लिए भुगतान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कम हो गए। प्रमुख सेक्टरों के बीच, भारत से विदेश यात्रा प्रतिबंधों के कारण समुद्रपार यात्रा के भुगतान में 55.9 प्रतिशत की कमी आई। साल-दर-साल आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में परिवहन सेवाओं के भुगतान (कुल सेवा आयात में 16 प्रतिशत की हिस्सेदारी) में 25.9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। व्यापार सेवा जो कुल सेवा आयात का 43.41 प्रतिशत थी, के आयात के भुगतान में वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 4.22 प्रतिशत की कमी देखी गई। व्यापार सेवा भुगतानों में कमी के प्राथमिक कारण व्यवसायी, प्रबंधन ओर परामर्श सेवाओं का निम्न आयात भुगतान था (तालिका 5)।

9.14 निर्यात की तुलना में सेवा आयात में तीव्र कमी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में शुद्ध सेवा प्राप्तियों को 2.1 प्रतिशत बढ़ा दिया। वाणिज्य वस्तु व्यापार घाटा में तीव्र संकुचन और स्थिर शुद्ध सेवा प्राप्तियों के कारण 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी का 3.9 प्रतिशत, चालू खाता अधिशेष था। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, हालांकि 2020² (जनवरी-मार्च) की पहली तिमाही में वैश्विक सेवा व्यापार में 4.3 प्रतिशत (साल-दर-साल की कमी आई है, लंकिन प्रमुख सेक्टरों में उछाल के संकेत दिखाई देने लगे हैं। 2020-21 की दूसरी तिमाही में सेवा क्षेत्र में भारतीय व्यापार पर अनंतिम डेटा, बहाली के संकेत दे रहे हैं, जिसमें निर्यात में 8.45 प्रतिशत की त्रैमासिक वृद्धि और आयात में 13.2 प्रतिशत की त्रैमासिक वृद्धि के परिणामस्वरूप शुद्ध सेवा निर्यात में 2.3 प्रतिशत का त्रैमासिक सुधार हुआ है। भले ही माल और सेवाओं के वैश्विक व्यापार पैमाने का अनुमान वर्ष 2021 के लिए आशावादी हो, लंकिन वैश्विक महामारी की रोकथाम और इसकी अवधि तथा अर्थव्यवस्था बहाली के लिए सरकारी नीति की प्रभावशीलता, वे महत्वपूर्ण कारक हैं जो भारतीय सेवा व्यापार को आकार देंगे।

प्रमुख सेवाएं: सबसेक्टरवार प्रदर्शन और नव नीतियां

9.15 कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 2020-21 के दौरान सेवा सेक्टर के अधिकांश सबसेक्टर्स के विकास में संकुचन देखा गया (तालिका 6)। 2020 में विमानन और पर्यटन में तेजी से गिरावट आई। गत वर्ष जनवरी-जून के दौरान 5.29 मिलियन की तुलना में 2020, जनवरी-जून के दौरान केवल 2.46 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत में आए। नतीजन, पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय 2020 की पहली छमाही के दौरान 6.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक घट गई, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में यह 14.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। घरेलू यात्री यातायात भी अप्रैल-नवंबर, 2020 में घटकर 22.77 मिलियन रह गया जो गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 95.7 मिलियन था। बंदरगाहों के क्षेत्र में, बंदरगाहों पर कार्गो यातायात अप्रैल-नवंबर, 2019 में 864.32 मीट्रिक टन की तुलना में अप्रैल-नवंबर की चालू घाटा अवधि के दौरान 10.09 प्रतिशत की कमी के साथ, 777.04 मिलियन टन (एमटी) रह गया। इस खंड में सेवा सेक्टर के कुछ महत्वपूर्ण सब-सेक्टरों में विकास पर विस्तृत चर्चा की गई है।

तालिका 6: भारतीय सेवा सेक्टर में महत्वपूर्ण सब-सेक्टरों का प्रदर्शन

नई-मबजवत	पद्धति-पंजीयता	न्देश	लम्त				
			2016.17	2017.18	2018.19	2019.20	2020.21
आईटी-बीपीएम*	आईटी-बीपीएम सेवा राजस्व	यूएस\$ मिलियन	139.9	151.4	161.8	174.53 (E)	—
	निर्यात	यूएस\$ मिलियन	116.1	125.1	135.5	146.6 (E)	—
	घरेलू	यूएस\$ बिलियन	23.8	26.3	26.3	28 (E)	—
उडडयन**	वायु यान यात्री	मिलियन	158.4	183.9	204.2	202 (P)	—
	घरेलू	मिलियन	103.7	123.3	140.3	141.6	22.77 [#]
	अंतरराष्ट्रीय	मिलियन	54.7	60.6	63.9	60.4	—
दूरसंचार	बेतार फोन अभिदान	मिलियन	1,170.2	1,183.4	1,161.8	1,157.8	1,151.81 ^{##}
	वायरलेस इंटरनेट अभिदान	मिलियन	400.6	472.7	582.8	720.7	—

2. सेवा व्यापार गतिविधि सूचकांक, वर्ल्ड ट्रेड बैरोमीटर डब्ल्यू टी ओ, सितंबर 17, 2020

	विदेशी यात्री आगमन	मिलियन	8.8	10.0	10.6	10.9 (P)	2.46###
पर्यटन	पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय	यूएस\$ मिलियन	22.9	27.3	28.6	30.1 (P)	6.16###
जहाजरानी	जहाजरानी की सकल टनभार	मिलियन	11.6	12.6	12.8	12.68^	12.75@
	जहाज की संख्या	मिलियन	1,316	1,384	1,405	1,431^	1,453^^
पोर्ट	पोर्ट ट्रैफिक	मिलियन टन	1,133.7	1,208.6	1,276.8	1307.2	777.04#
	कार्गो क्षमता	मिलियन टन	2,147.6	2,307.4	2,405.9	2,522.9	2,529.1(P)

स्रोत: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई), दूरसंचार विभाग, पर्यटन मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नॉस्कोम।

नोट: हार्डवेयर सहित और ई-कॉमर्स को छोड़कर; 'निर्धारित घरेलू सेवाओं पर निर्धारित भारतीय विमान वाहकों द्वारा घरेलू यात्रियों की यात्रा और भारत से आने तथा जाने के लिए निर्धारित भारतीय और विदेशी विमान वाहकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की यात्रा; क: निश्चित वित्तीय वर्ष में मार्च से; ख: कैलेंडर वर्ष के आधार पर; #अप्रैल-नवंबर 2020 की अवधि के दौरान ###अक्टूबर 2020 तक ####जनवरी से जून 2020 @ जून 2020 को ^ मार्च 2020 तक ^^ नवंबर 2020 तक p अनंतिम E प्रत्याशित

पर्यटन सेक्टर

9.16 जीडीपी, विदेशी मुद्रा अर्जन और रोजगार के रूप में पर्यटन सेक्टर, आर्थिक विकास का एक प्रमुख इंजन है जो महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि, भारत सहित विश्व यात्रा और पर्यटन पर कोविड-19 महामारी का दुर्बल प्रभाव पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व पर्यटन संगठन (दिसंबर, 2020 संस्करण) के विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार यात्रा पर प्रतिबंधों, अल्प उपभोक्ता विश्वास और कोविड वायरस नियंत्रण में वैश्विक संघर्ष के कारण, 2020 के प्रथम दस माह में अंतर्राष्ट्रीय आगमन वैश्विक रूप में 72 प्रतिशत गिरा, कुल मिलाकर यह पर्यटन इतिहास में रिकार्ड सबसे खराब वर्ष रहा। जनवरी-अक्टूबर 2019 की तुलना में इस वर्ष जनवरी-अक्टूबर में विश्व पर्यटन स्थलों पर 900 मिलियन कम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक पहुंचें, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से प्राप्त निर्यात राजस्व में 935 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा हुआ। ध्यान दें कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आईटीए), 2019 में कुल 1.5 बिलियन तक पहुंच गया।

9.17 वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, भारतीय हवाई क्षेत्र नियामक, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मार्च 2020 में सभी व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोक दिया था। इस प्रतिबंध को जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया है। कोविड-19 महामारी के फैलाव और इसके परिणामस्वरूप विश्व भर में लगाए गए लॉकडॉउन के बाद विदेशों में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए, मई की शुरूआत में वंदे भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। इस मिशन, जो अभी अपने नौवें चरण में है, के तहत सरकार ने अपने नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए अन्य देशों के साथ ट्रांसपोर्ट बबल्स³ स्थापित किए हैं। वर्तमान में भारत 24 देशों के साथ सक्रिय एयर बबल्स रखा है। वंदे भारत मिशन के शुभारंभ से 5 जनवरी, 2021 तक विभिन्न एयरलाइनों द्वारा 4.49 मिलियन से अधिक लोगों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा का लाभ प्राप्त हुआ।

9.18 2017 में, 10.04 मिलियन विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) में 14 प्रतिशत वृद्धि और 27.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा अर्जन (एफईई) में 19.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारत में पर्यटन सेक्टर

3.“ट्रांसपोर्ट बबल्स” या “हवाई यात्रा व्यवस्थाएं”, व्यापारिक यात्री सेवाओं को पुनः प्रारंभ करने के उद्देश्य से दो देशों के मध्य अस्थायी व्यवस्थाएं हैं जबकि कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक है। ये पारस्परिक प्रकृति के होते हैं, जिसका अर्थ है दोनों देशों की एयरलाइनों को समान लाभ प्राप्त होंगे।

ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि, 2020 में तीव्र गिरावट से पूर्व, 2018 और 2019 में सेक्टर मंदी से गुजर रहा था (चित्र 2 (क और ख))। 2018 में 10.56 मिलियन की तुलना में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए), 2019 में 10.93 मिलियन था। विकास के संदर्भ में, एफटीए की वृद्धि दर, 2017 में 14 प्रतिशत के 2018 में 5.2 प्रतिशत और बाद में 2019 में 3.5 प्रतिशत हो गई। पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन (एफईई), 2018 में 28.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2019 में 30.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। विकास के संदर्भ में, एफईई, 2017 में 19.1 प्रतिशत के 2018 में 4.7 प्रतिशत गिरा और 2019 में 5.1 प्रतिशत के साथ थोड़ा सा सुधार हुआ।

9.19 2018 में 22वें स्थान से थोड़ा सा गिरकर, 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन के संदर्भ में भारत दुनिया में 23वां स्थान पर रहा। देश, दुनिया के 1.23 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन और एशिया एवं प्रशांत के 4.97 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन पर नियंत्रण रखता है (तालिका 7)। भारत पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जन के संदर्भ में दुनिया में 12वां और एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में 7वां स्थान रखता है, जो दुनिया के पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जन का 2 प्रतिशत से अधिक हैं।

तालिका 7: भारत और विश्व में विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन तथा पर्यटन प्राप्तियां

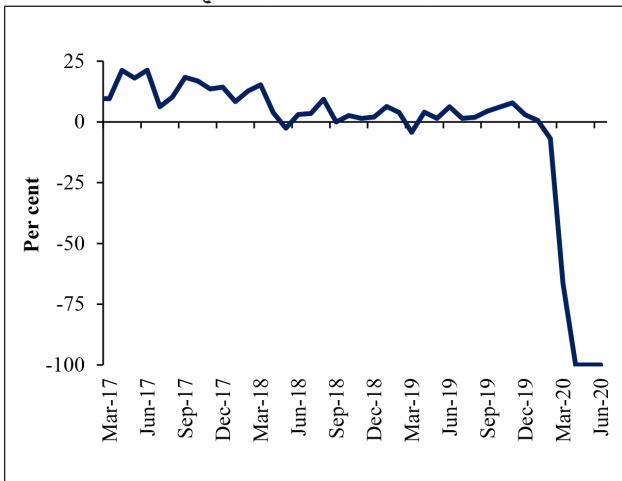
चंडमजमत	2015	2016	2017	2018	2019
भारत में विदेशी पर्यटन आगमन (एफटीए) (मिलियन)	8.03	8.80	10.04	10.56	10.93
भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन (आईटीए) (मिलियन)*	13.76	15.03	16.81	17.42	17.91
विश्व के आसपास अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन (आईटीए) (मिलियन)	1,195	1,241	1,333	1,408	1,460
विश्व आईटीए में भारत का शेयर (प्रतिशत)	1.15	1.21	1.26	1.24	1.23
विश्व आईटीए में भारत का रैंक	24 th	26 th	26 th	2 nd	23 rd
एशिया और प्रशांत में आईटीए (मिलियन)	284.1	306.6	324.1	347.7	360.1
एशिया प्रशांत महासागरीय में भारत का शेयर (प्रतिशत)	4.84	4.90	5.19	5.01	4.97
एशिया प्रशांत महासागरीय में भारत का रैंक	7 th	8 th	7 th	7 th	7 th
विश्व पर्यटन प्राप्तियाँ में भारत का शेयर (प्रतिशत)	1.73	1.84	2.02	1.97#	2.03#
पर्यटन के माध्यम विदेशी मुद्रा अर्जन (यूएस \$ मिलियन)	21.01	22.92	27.31	28.59	30.06
विश्व पर्यटन प्राप्तियां से भारत का रैंक	14 th	13 th	13 th	13 th #	12 th #
एशिया प्रशांत महासागरीय पर्यटन प्राप्तियों में भारत का शेयर (प्रतिशत)	5.91	6.18	6.89	6.55#	6.57#
एशिया प्रशांत महासागरीय पर्यटन प्राप्तियों में भारत का रैंक	7 th	7 th	7 th	7 th #	6 th #

स्रोत: पर्यटन मंत्रालय।

टिप्पणी: सभी आंकड़े कैलेंडर वर्षवार हैं।

* अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन इस देश में विदेशी पर्यटन आगमन और एन.आर.आई. आगमन का कुल योग, #अनंतिम

चित्र: 2(क): भारत के विदेशी पर्यटन आगमन में
वृद्धि (वर्ष वार वर्ष)



स्रोत: पर्यटन मंत्रालय।

टिप्पणी: 2020 के आंकड़े अनंतिम हैं।

मार्च, 2020 से सभी अंतर्राष्ट्रीय बाणिज्यिक उड़ानों को स्थगित कर दिया गया है।

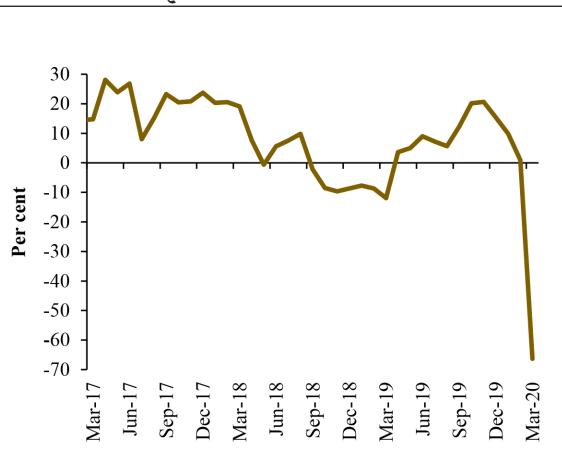
9.20 भारत में घूमने के लिए आने वाले शीर्षस्थ 10 देशों से आए विदेशी पर्यटक बांगलादेश, यू.एस.ए., यू.के., ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, मलेशिया, श्रीलंका, जर्मनी और रूस से हैं। 2019 में भारत में कुल विदेशी पर्यटक आगमन 67 प्रतिशत था। विदेशी पर्यटकों में से 57% प्रतिशत पर्यटक आराम करने, छुटियाँ बिताने और मनोरंजन के लिए घूमने आए थे, 14.7% प्रतिशत व्यवसाय के उद्देश्य से यहां आए थे। और 12.7 प्रतिशत भारतीय डायसपोरा थे।

9.21 राज्य के स्तर पर पर्यटन संबंधी रूझानों के देखने पर, घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष पांच राज्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं, जो वर्ष 2019 में इस देश में घूमने आने वाले कुल घरेलू पर्यटक का लगभग 71 प्रतिशत था। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष पांच राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल हैं। जिनकी संख्या वर्ष 2019 में इस देश में घूमने वाले कुल विदेशी पर्यटकों का 69.4 प्रतिशत थी।

9.22 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को सहयोग देने के लिए, भारत ने 46 देशों के लिए सितम्बर 2014 में ई.-टूरिस्ट विज़ा पद्धति प्रारम्भ किया है। इस योजना को आरम्भ करने से पहले, केवल 12 देशों के लिए ही ई.-विज़ा की सुविधा उपलब्ध थी। सरकार ने आगे 2016 में विज़ा पद्धति का ‘ई.-टूरिस्ट विज़ा’ ‘ई.-विजेनेस विज़ा’ ‘ई.-मेडिकल विज़ा’ ‘ई.-कॉफ्रेंस विज़ा’ और ‘ई.-मेडिकल अटेंडेंट विज़ा’ जैसे पांच उप-वर्गों वाले ई.-विज़ा योजना का पुनः नामकरण करते हुए, इसे उदार बनाया। ई.-विज़ा योजना 28 नामोदिष्ट हवाई अड्डों और 5 नामोदिष्ट समुद्र पत्तन के जरिए वैध प्रविष्टि के साथ 169 देशों के लिए उपलब्ध है। इसके साथ, ई.-विसा पर भारत में विदेशी पर्यटक के आगमन में 2015 में 4.45 लाख से 2019 में 29.28 लाख की वृद्धि हुई, और जो जनवरी-मार्च 2020 में 8.37 लाख तक बरकरार रही थी।

9.23 भारत 2013 में अपने 65वें स्थान से उल्लेखनीय रूप से सुधार करते हुए, यात्रा और पर्यटन प्रतियोगितात्मकता सूचकांक में 34वां स्थान प्राप्त किया है। पर्यटन ने 2018-19 में भारत की कुल जी.डी.पी. का 5 प्रतिशत शेयर का योगदान दिया है। यह भारत में कुल रोज़ग़ार का लगभग 13 प्रतिशत की सहायता भी प्रदान करता है।

चित्र: 2(ख): पर्यटन विदेशी विनियम अर्जन में
वृद्धि (वर्ष वार वर्ष)



आई.टी.-बी.पी.एम. सेवा

9.24 भारतीय आई.टी.-बी.पी.एम. उद्योग अंतिम वर्षों से भारत के निर्यात का ध्वज-वाहक रहा है। जबकि 1999-2000 से 2009-10 वृद्धि का दशक था, इसका अंतिम दशक, इसके एकीकरण और उद्योग को राजस्व और कर्मचारी वृद्धि को अलग करने में स्ल रहा है। गत दशक से, इस उद्योग में 2019-20 में राजस्व का 190.5 यू.एस.+बिलियन डॉलर के आकार तक पहुँच कर 102 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। इसमें गत 10 वर्षों से 70 प्रतिशत तक वृद्धि कर 1.8 मिलियन कर्मचारियों को शामिल भी किया गया हैं हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में व्यवसास मॉडल में परिवर्तन आया है। चार्ट 1 में गत दो दशकों से आई.टी. और आई.टी. समर्थकृत सेवाओं के लिए व्यवसाय संबंधी मॉडल के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत है।

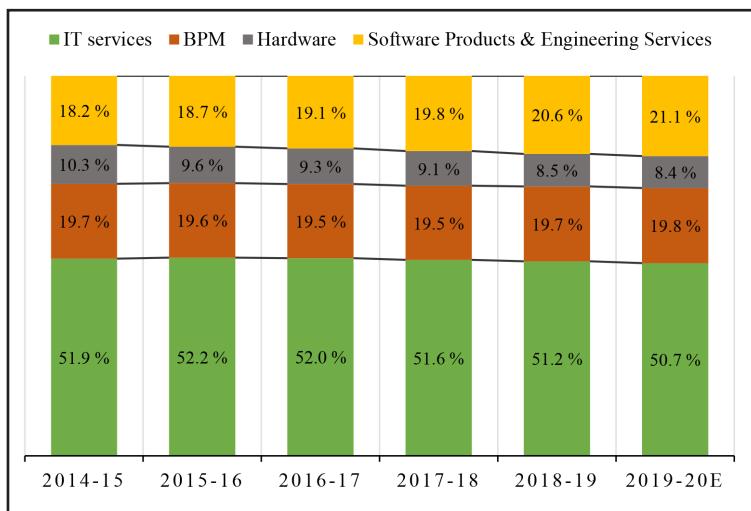
चार्ट 1:-आई.टी.-आई.टी.इ.एस. के लिए व्यवसाय के मॉडल का विकास

Dimensions	Customer Centric		Customer + Collaboration	
	1990	2000	2010-2015	2016-2020
Services	One client, one solution	Enterprise Services	Enterprise Solutions	Digital Enterprise products & solutions
Service Delivery	Custom, People Driven	Industrialised capacity & Method-driven	Capacity & IP driven	Platforms & Automation
Technology	Mainframe to Client Server	Y2K, dotcom enablement	Cloud, virtualisation, Mobile computing	Digital Tech (AI, ML/NLP, IoT, Blockchain)
Pricing	Input-based, Fixed Costs	Output-based, Fixed Costs or Gain share	Pay-per-use	Outcome-based
Deal structure	Deals relating to CAD/M & Maintenance	Multiple vendors, Large size, Long duration	Small deal wins, Short duration, End-to-end	Structured deals, Internet focused transactions
Resources	Staff-augmentation	Fixed Capacity	Non-linear	Humans+Machines, Domains & Tech Experts
Time to Deploy	Years	Months	Weeks or Days	Continuous Releases

स्रोत: एन.ए.एस.एस.सी.ओ.एम. (नैस्कॉम)

9.25 गत छह वर्षों से, आई.टी. संबंधी सेवाओं ने 2019-20 में लगभग 97 बिलियन यू.एस. डॉलर के राजस्व के साथ, आई.टी.-बी.पी.एम. से सेक्टर (चित्र 3) का बहुतायत शेयर (50 प्रतिशत से अधिक) बरकरार रखा है। साफ्टवेयर व इंजिनियरी सेवाएं 2019-20 में इस क्षेत्र में 21 प्रतिशत का शेयर और 40.2 बिलियन यू.एस. डॉलर का राजस्व संघटित कर प्रत्येक वर्ष एक अनवरत वृद्धि का साक्ष्य रही हैं। जी.पी.एम. सेवाओं ने 19.8 प्रतिशत अपना शेयर बरकरार रखा है, जबकि हार्डवेयर सेवाओं में प्रत्येक वर्ष के शेयर में कमी रही है लेकिन इसने राजस्व में वृद्धि बरकरार रखा है।

चित्र 3: 2014-15 से 2019-20 में आई.टी.-बी.पी.एम. क्षेत्र का उप-क्षेत्रों का अलग-अलग आंकड़े।



स्रोत:- एन.ए.एस.एस.सी.ओ.एम. (नैस्कॉम) टिप्पणी: ई.: प्राक्कलन

9.26 आई.टी.-बी.पी.एम. उद्योग (हार्डवेयर और ई.-कॉर्मर्स को छोड़कर) का महत्वपूर्ण भाग (लगभग 84 प्रतिशत) 2019-20 में 146 बिलियन यू.एस. डॉलर से अधिक निर्यात राजस्व के साथ (तालिका 8) इसे निर्यात चालित रखना कायम रहता है। 2019-20 के दौरान, आई.टी.-बी.पी.एम. सेक्टर (हार्डवेयर और ई.-कॉर्मर्स को छोड़कर) के लिए राजस्व वृद्धि के लिए (वर्षावार) 2018-19 में 6.8 प्रतिशत से 7.9 प्रतिशत तक पहुंचने के लिए वसूली की गई थी। घरेलू राजस्व वृद्धि में (2018-19) में -0.3 प्रतिशत से 2019-20 में 6.6 प्रतिशत तक) एक महत्वपूर्ण उछाल द्वारा इसे मुख्य रूप से चालित किया गया था।

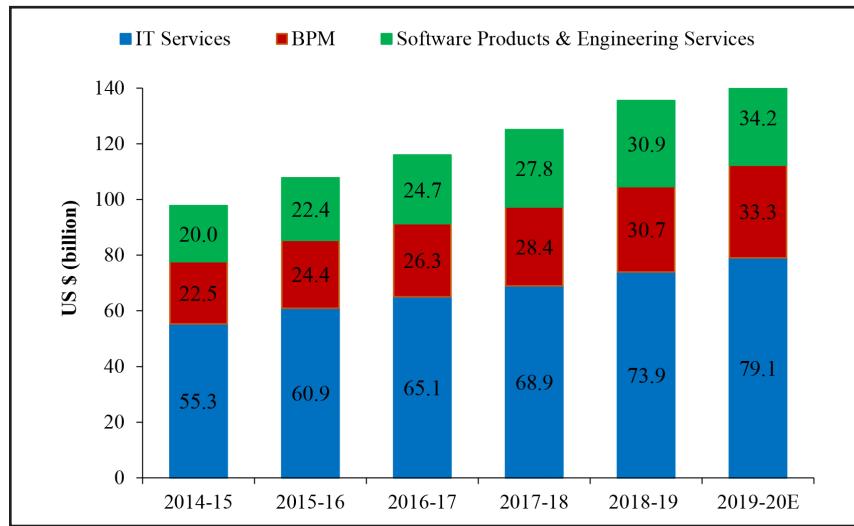
तालिका 8: भारतीय आई.टी.-बी.पी.एम. उद्योग -हार्डवेयर और ई.-कॉर्मर्स को छोड़कर) के निर्यात और बाज़ार का आकार

Year	USD billion			Per cent (YoY)		
	Domestic	Exports	Total	Domestic	Exports	Total
2015-16	21.58	107.83	129.41	3.2	10.3	9.1
2016-17	23.84	116.06	139.90	10.4	7.6	8.1
2017-18	26.33	125.08	151.40	10.4	7.8	8.2
2018-19	26.25	135.51	161.76	-0.3	8.3	6.8
2019-20E	27.99	146.55	174.53	6.6	8.1	7.9

स्रोत:-नैस्कॉम। टिप्पणी: ई.: प्राक्कलन।

9.27 वर्ष 2019-20 में आई.टी.-बी.पी.एम. सेक्टर के निर्यात में कुल 146.55 बिलियन यू.एस. डॉलर में से आई.टी. सेवाओं ने 54 प्रतिशत निर्यात का हिसाब लगाते हुए 79.1 बिलियन यू.एस. डॉलर का योगदान दिया है। (चित्र-4) बी.पी.एम. और सॉफ्टवेयर उत्पादों व इंजिनियरी सेवाओं को लगभग 23 प्रतिशत के करीब समान (बराबर) शेयर के लिए प्रत्येक लेखाकरण के साथ बचे हुए 46 प्रतिशत हिसाब में लिया गया है। सभी तीनों उप-क्षेत्रों ने आई.टी. सेवाओं में 6.9 प्रतिशत तक, बी.पी.एम. सेवाओं में 8.4 प्रतिशत तक और सॉफ्टवेयर उत्पादों व इंजिनियरी सेवाओं में 10.7 प्रतिशत के साथ वर्षावार 2019-20 के निर्यात संबंधी राजस्व में वृद्धि का साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

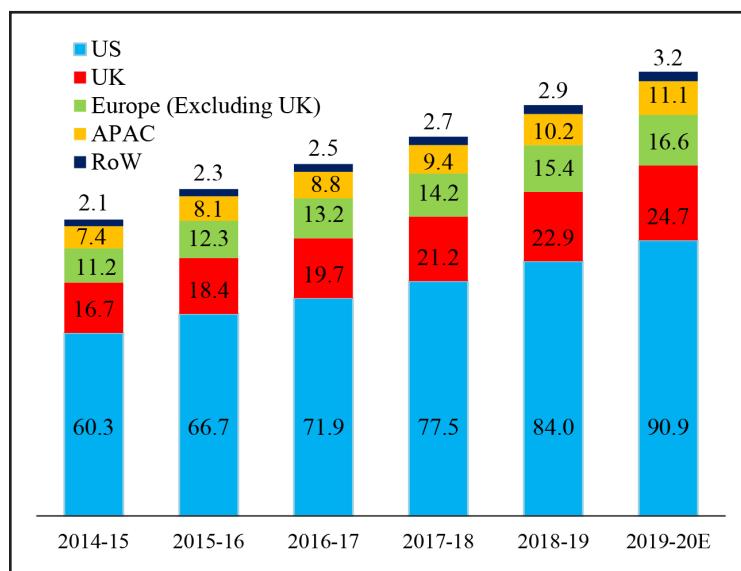
**चित्र 4: आईटी.-बी.पी.एम. संबंधी निर्यात (यू.एस. बिलियन डॉलर) के उपक्षेत्र का विघटन
(हार्डवेयर और ई.-कॉमर्स को छोड़कर)**



स्रोत: नैस्काम। टिप्पणी: ई.: प्राक्कलन।

9.28 निर्यात संबंधी राजस्व के वितरण को देश-वार देखने पर, 91 बिलियन यू.एस. डॉलर के कुल योग के साथ यू.एस.ए. निर्यात का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना रहा है (चित्र 5), जिसका 2019-20 में कुल आईटी.-बी.पी.एम. निर्यात (हार्डवेयर को छोड़कर) का 62 प्रतिशत हिसाब लगाया गया है। इसके बाद यू.के. के आता है, जो 24.7 बिलियन यू.एस. डॉलर लेकिन लगभग 17 प्रतिशत कुछ कम शेयर के साथ आईटी.-बी.पी.एम. सेवाओं के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। यूरोप (यू.के. को छोड़कर) और एशिया प्रशांत महासागरीय के लिए क्रमशः भारत के निर्यात संबंधी उपार्जन का 11.4 प्रतिशत और 7.6 प्रतिशत का हिसाब लगाया गया है।

**चित्र 5: भारत के आईटी.-बी.पी.एम. संबंधी निर्यात (बिलियन यू.एस. डॉलर)
(हार्डवेयर और ई.-कॉमर्स को छोड़कर) का भौगोलिक विश्लेषणात्मक विवरण**



स्रोत: नैस्काम। टिप्पणी: ई.: प्राक्कलन।

9.29 2021 में, ओ.एस.पी. की शर्तों में और उपभोक्ता संरक्षण (ई.-कॉर्मस) नियम, 2020, में रियायत के साथ आईटी.-बी.पी.एम. सेक्टर में नवप्रवर्तन, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और दक्षता को चालित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। इससे प्रतिभा में प्रवेश संबंधी महत्वपूर्ण तरीके से प्रसार, जॉब सर्जन में वृद्धि, भारत को एक वैश्विक केंद्र (हव) बनाने और इस क्षेत्र को वृद्धि और नवप्रवर्तन के अगले स्तर तक शिला प्रक्षेप करने में सहायता मिलेगी। अधिक विवरण के लिए बॉक्स 1 देखें।

9.30 कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के बावजूद, भारतीय स्टार्ट-अप परितंत्र में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। इस परितंत्र ने विश्वव्यापी महामारी के आक्रमण (चढ़ाई) के अनगिनत चुनौतियों का सामना करते हुए, विषमताओं का सामना किया और 12 ऐसे स्टार्ट-अप्स का रिकॉर्ड बनाया, जो यूनिकॉर्न स्टेट्स पर पहुँचे हैं। नैस्कॉम टेक स्टार्ट-अप रिपोर्ट 2021 के अनुसार, फिलहाल (वर्तमान में) यह देश 38 यूनिकॉर्न का ठिकाना (केंद्र) है। यू.एस. और चीन के पास क्रमशः 243 और 227 यूनिकॉर्न्स हैं।

बॉक्स 1:-आईटी.-बी.पी.एम. सेक्टर की नीति संबंधी प्रमुख पहलकदमियाँ और सुधार

ओ.एस.पी. की शर्तों में रियायत: आईटी. उद्योग विशेषकर व्यवसाय प्रक्रिया के लिए बाहरी स्रोत से सेवाएं प्राप्त करने (बी.पी.ओ.) और आईटी. द्वारा समर्थकृत सेवाओं से संबंधित व्यवसाय को करने की सुगमता में सुधार करने के लक्ष्य के साथ, नवम्बर, 2020 में, सरकार ने दूरसंचार विभाग को अन्य सेवा प्रदाता (ओ.एस.पी.) के दिशा-निर्देशों को सरल किया है। नए दिशा-निर्देशों ने बी.पी.ओ. उद्योग के अनुपालन संबंधी भार में पर्याप्त रूप से कमी की है और जिसके द्वारा 'वर्क फ्रॉम होम' को समर्थ किया गया है।

वस्तुतः, अन्य सेवा प्रदाताओं (ओ.एस.पी.) पंजीकरण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया था, और डेटा संबंधी परिचालनों में नियुक्त व्यवसाय प्रक्रिया संबंधी आउटसोर्सिंग (बी.पी.ओ.) को ओ.एस.पी. की परिधि से बाहर लाया गया है। इसके अलावा, बैंक प्रत्याभूति जमा, अपरिवर्ती आई.पी. की आवश्यकता, रिपोर्टिंग संबंधी नियमित वाध्यता, नेटवर्क आरेख का प्रकाशन, दंड संबंधी उपबंध आदि जैसी अन्य आवश्यकताओं को दूर भी किया जाएगा। ये परिवर्तन आईटी.-बी.पी.एम. कम्पनियों को 'वर्क फ्रॉम होम' तथा 'वर्क फ्रॉम एनिव्हेयर' को समर्थ करेंगे। इस उद्योग के लचीलेपन में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त छूट दी गई है। यह नया ढाँचा भारत के उद्योग को दृढ़ आवेग प्रदान कर भारत को विश्व में सबसे प्रतिस्पर्धात्मक आईटी. अधिकार-क्षेत्र में से एक बनाएगा।

उपभोक्ता संरक्षण-अधिनियम, 2019: यह अधिनियम उपभोक्ताओं के समर्थ बनाते हुए 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ है और यह उन उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता विवाद सुधार आयोग, मध्यस्थता, उत्पाद देयता और मिलावट/अवैध माल बाले उत्पाद के विनिर्माण या उनकी बिक्री की सज़ा जैसे इनके भिन्न-भिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों को संरक्षित करने में सहायता करता है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और इन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सी.सी.पी.ए.) की स्थापना करना समिलित होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ई.-कॉर्मस सत्त्व से उत्पादन देश सहित वापसी, रिफंड, विनियम, वारंटी और गारंटी, सुपर्दी, भुगतान का तरीका, शिकायत निवारण प्रणाली, भुगतान, चार्ज बैंक विकल्प, आदि से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है, जो कि उपभोक्ता को इसके प्लेटफॉर्म के क्रय से पहले के चरण पर सूचित निर्णय लेने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, यह नया अधिनियम उत्पाद देयता के सिद्धांत का परिचय देकर अपने क्षेत्र के भीतर भरपाई हेतु किसी भी दावे के लिए उत्पाद विनिर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता और उत्पाद विक्रेता को लाता है। उपभोक्ता कार्य विभाग (डी.ओ.सी.ए.) ने जुलाई 2020 में उपभोक्ता संरक्षण (ई.-कॉर्मस) नियम,, 2020 प्रकाशित किया।

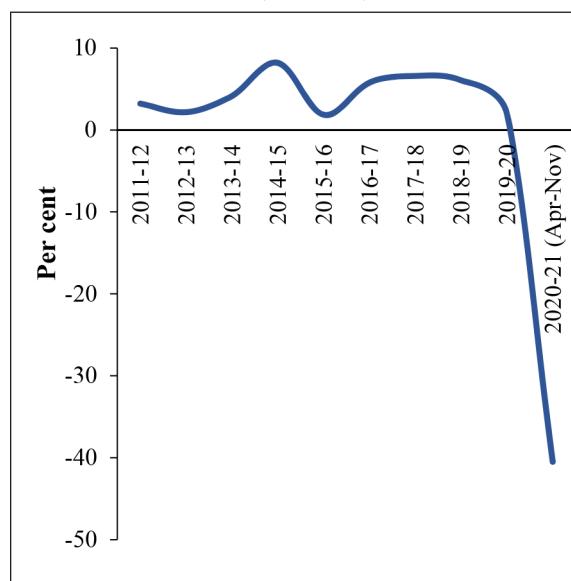
बंदरगाह, नौपरिवहन और जलमार्ग सेवाएँ:-

9.31 बंदरगाह यात्र के अनुसार भारत में लगभग 90 प्रतिशत निर्यात-आयात की खेप और मूल्यानुसार 70 प्रतिशत खेप को सम्भालते हैं। जिन प्रमुख बंदरगाहों की कुल कार्गो क्षमता मार्च 2014 के अंत तक 871.52 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.) थी, उसमें मार्च 2020 के अंत तक 1,534.91 मैट्रिक टन प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है, इन बंदरगाहों ने 2019-20 के दौरान 704.92 एम.टी. की ट्रैफिक को सम्भाला है। दीनदयाल (कोंडला), पारादीप, जे.एन.पी.टी., विशाखापटनम और चेन्नई सहित इन बंदरगाहों में मार्च 2020 की स्थिति

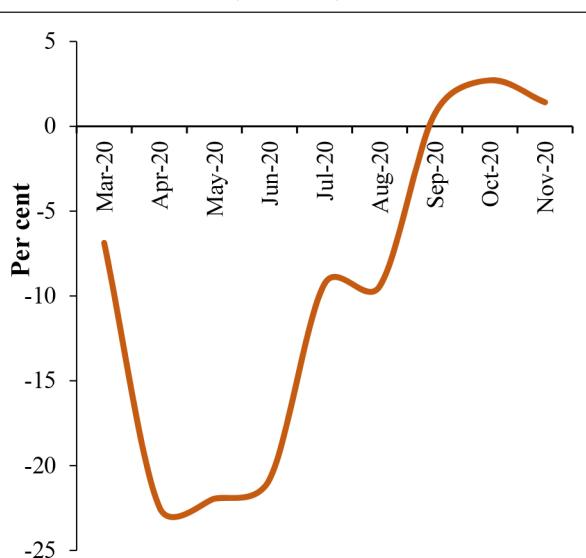
के अनुसार सर्वाधिक कार्गो क्षमता थी। जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के पास विश्व पोतावली में एक प्रतिशत का शेयर है। भारतीय कम्पनियों द्वारा खरीदे गए जहाज़ों की कुल संख्या 2014-15 में 1210 से 2019-20 में 1431 तक रहा।

9.32 2015-16 और 2018-19 के बीच बंदरगाह संबंधी सम्पूर्ण ट्रैफिक में लगभग 6 प्रतिशत की अनवरत वृद्धि बरकरार थी। कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के आने से लॉकडाउन के कारण 2020 में तेज़ी से गिरने से पहले, यह 2019-20 में 1.98 प्रतिशत तक की मंदी आई। कार्गो ट्रैफिक की वृद्धि अप्रैल से जून 2020 के बीच पर्याप्त संकुचित हुई है, हालांकि जिसमें सुधार के संकेत दिख रहे हैं। वस्तुतः, सितम्बर 2020 से कार्गो ट्रैफिक की वृद्धि में सकारात्मक मोड़ आया है।

(चित्र 6 (क): पोर्ट ट्रैफिक में वार्षिक वृद्धि
(वर्षवार)



(चित्र 6 (ख): पोर्ट ट्रैफिक में मासिक वृद्धि
(वर्षवार)



स्रोत: बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

9.33 जहाजों का टर्न अराउंड (मोड़ का) समय, जो पत्तन क्षेत्र की क्षमता का एक महत्वपूर्ण सूचक है, उसमें 2014-15 में 4 दिनों से 2020-21 (अप्रैल-सितम्बर) में 2.62 दिनों तक की कमी आई है। पोत-परिवहन के टर्न अराउंड समय में सभी मुख्य बंदरगाहों में कमी आई है, जोकि कोचीन बंदरगाह पर सबसे कम और मोरमुगाओं बंदरगाह में सबसे अधिक है (तालिका 9)। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी प्रमुख बंदरगाहों में से पारादीप बंदरगाह ने 2014-15 में 7 दिनों से अधिक दिन से 2020-21 (अप्रैल-सितम्बर) में 3 दिनों से कम तक के जहाज के औसतन टर्न अराउंड समय में कमी के साथ अत्यधिक सुधार दर्शाया है। यू.एन.सी.टी.ए.डी. के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, विश्व में जहाज का मध्यिका टर्न अराउंड समय 0.97 दिन है, जो यह सुझाव प्रस्तुत करता है कि भारत के पास बंदरगाहों की क्षमता में और भी अधिक सुधार करने की जगह है।

तालिका 9: प्रमुख भारतीय बंदरगाहों पर जहाज़ का औसत टर्न अराउंड समय (दिनों में)

बंदरगाह	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (अप्रैल-सितम्बर)
कोलकाता	4.18	3.98	4.73	4.11	3.84	4.21	3.09
हल्दिया	3.37	3.27	3.45	3.76	3.04	3.62	3.07

चौ	2014.15	2015.16	2016.17	2017.18	2018.19	2019.20	2020.21 (चतुर्वेदी मंचज)
पारादीप	7.01	4.50	4.99	3.31	2.51	2.98	2.76
विशाखापट्टनम	5.67	3.84	3.75	2.58	2.51	2.48	2.67
कामाराजर (एन्नोर)	4.32	6.53	2.70	2.20	1.97	1.85	1.90
चैन्नई	2.54	2.53	2.51	2.21	1.98	2.00	2.22
बी.ओ. चिदम्बरनर	3.55	3.73	4.40	2.69	1.96	2.01	2.14
कोचीन	1.69	2.18	1.99	1.54	1.47	1.51	1.66
न्यू मंगलोर	2.46	2.63	2.35	2.04	1.93	1.91	2.05
मोरमुग्गाओ	4.15	3.65	4.51	2.63	2.63	2.69	3.94
मुम्बई	5.28	4.61	3.27	3.72	2.52	2.56	2.96
जे.एन.पी.टी.	2.24	2.44	2.01	2.24	2.13	2.00	2.12
दीनदयाल (कांडला)	5.38	4.66	4.40	2.51	3.01	2.94	3.27
सभी प्रमुख बंदरगाह	4.00	3.64	3.43	2.68	2.48	2.59	2.62

स्रोतः—बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

9.34 14,500 किलोमीटर की अंतर्रिहित नौ-गम्य तटरेखा और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्रवर्ती व्यापार मार्गों के कारोबार-स्थानों को उपयोग में लाने के लिए सरकार ने उच्चाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिससे देश में पत्तन सृजन और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इस कार्यक्रम की विलक्षणता यह है कि आयात-निर्यात तथा घरेलू व्यापार की संभार-तंत्र संबंधी लागत को आधारभूत संरचना में न्यूनतम निवेश के साथ घटाया जाए। इसमें घरेलू कार्गो (पोत-भार) की लागत का कम किया जाना; तट के निकट भावी औद्योगिक क्षमताओं के निर्धारण द्वारा थोक पण्यपदार्थ की संभार-तंत्र संबंधी लागत का कम किया जाना; पत्तन समीपस्थ विभिन्न परिष्कृत उत्पादों के सृजन और संयोजन के क्षेत्र के विकास द्वारा निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार लाना आदि सम्मिलित हैं। सागरमाला कार्यक्रम में कुल 504 परियोजनाओं की पहचान चार स्तरों के अंतर्गत की गई है, जोकि इस प्रकार हैं – 211 पत्तन आधुनिकीकरण परियोजनाएं-199 पत्तन संयोजन परियोजनाएं-32 पत्तन सृजन और विकास आधारित औद्योगीकरण परियोजनाएं तथा 62 तटीय संप्रदाय विकास परियोजनाएं, जिनके द्वारा पत्तन सृजन और विकास संभावनाएं प्रकट हो जाएंगी और ऐसा अपेक्षित है कि 3.57 लाख करोड़ से अधिक का आधारभूत संरचना निवेश जुटाया जा सकेगा। जुलाई 2019 से अक्टूबर 2020 की अवधि में 4,543 करोड़ रुपए की 20 सागरमाला परियोजनाएं संपूर्ण हो चुकी हैं जिनमें 1405 करोड़ रुपए की पत्तन-आधुनिकीकरण की 9 परियोजनाएं, 2799 करोड़ रुपए की पत्तन संयोजन की 7 परियोजनाएं तथा 339 करोड़ रुपए की तटीय समुदाय विकास की 4 परियोजनाएं समाविष्ट हैं।

अंतरिक्ष क्षेत्र

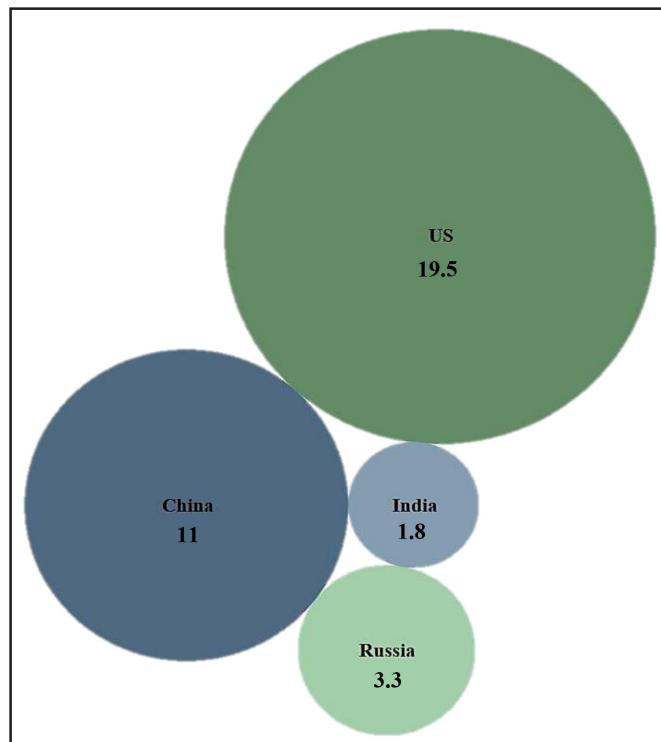
9.35 पिछले छह दशकों में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में चरघातांकी वृद्धि हो चुकी है जिनमें 1960 के दशक की सामान्य स्पेस-मैपिंग सेवाओं से लेकर अब तक अनेक प्रकार के विविध उपयोग किए जा रहे हैं जिनमें प्रेक्षण यानों की अभिकल्पना और विकास की श्रृंखला तैयार करना तथा संबंधित प्रौद्योगिकी, भू-प्रेक्षण के लिए उपग्रह और संबंधित प्रौद्योगिकियां, दूरसंचार और ब्रॉड-बैंड, दिक्कालन, मौसम-विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान और विकास और सबसे निकटवर्ती समय में ग्रहीय-गवेषण सम्मिलित हैं।

9.36 वर्ष 2019-2020 में भारत ने लगभग 1.8 बिलियन यूएस डॉलर का व्यय अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर किया था, तथापि हमारा देश अभी भी इस क्षेत्र में बड़े देशों से पीछे है जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जिसने भारत

से लगभग 10 गुना अधिक धन का व्यय वर्ष 2019-2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में किया है (चित्र-7), और चीन जिसने भारत से लगभग 6 गुना अधिक का व्यय किया है।

9.37 भारत ने हाल के वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 5 से 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। दूसरी ओर यूएसए, रूस और चीन ने वर्ष 2019 में क्रमशः 19,25 और 34 उपग्रहों को छोड़कर उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के क्षेत्र में अभी भी बढ़त बना रखी है। (तालिका 10)

चित्र-7: व्यय (वर्ष 2019-2020 में, बिलियन यूएस डॉलर में)



स्रोत: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)

तालिका 10: देश द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या

देश	2015	2016	2017	2018	2019
यूएसए	20	22	29	31	19
रूस	29	19	20	20	25
चीन	19	22	18	39	34
यूरोपियाई अन्तरिक्ष एजेंसी	9	9	9	8	6
भारत	5	7	5	7	6
जापान	4	4	7	6	2
अन्य	3	2	2	3	10
कुल	89	85	90	114	102

स्रोत: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)

बॉक्स 2: अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यवसायीकरण और निजी निवेश को आकर्षित करने की संभावनाएं

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया में सुविकसित कार्यक्रमों में से एक है और इसने अपने राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के माध्यम से कई सफलताएं प्राप्त की हैं, जो भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों को चलाने के लिए जिम्मेदार है। देश को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ, जून 2020 में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को खोल दिया, जिससे भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियां अंतरिक्ष गतिविधियों के समग्र क्षेत्र में भागीदार बन सकें। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रौद्योगिकियों की जानकारी का अन्यत्र उपयोग करने और भारतीय उद्योग को उच्च-प्रौद्योगिकियों विनिर्माण आधार को प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बनाया गया है। भारत सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) की भी स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, इसरो अपनी स्पिन-ऑफ नीतियों के आधार पर उत्पादन के लिए आधारभूत-संरचना को साझा करेगा, और प्रौद्योगिकी की जानकारी देगा। इन उपायों से भारत को अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का विनिर्माण केंद्र बनने में सहायता प्राप्त होगी।

उद्योग के अनुमानों के अनुसार, भारत में अंतरिक्ष और उपग्रह परियोजनाओं में पूंजी, कार्मिक-दल और आधारभूत-संरचना तीनों के साथ 40 से अधिक नव-उद्यम (स्टार्ट-अप) काम कर रहे हैं, जो सरकार के प्रयासों की सहायता करते हैं। आने वाले वर्षों में इस संख्या के बढ़ने की संभावना है जिसमें प्रौद्योगिकी एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में भारत की अंतरिक्ष क्षमता को खोलने के लिए किए गए सुधारों की घोषणा भारत की अंतरिक्ष यात्रा में निजी उद्योग को सह-यात्री बनाने में सक्षम बनाने की आवश्यकता पर बल देती है।

सैटेलाइट इंडस्ट्री एसोसिएशन की रिपोर्ट (2020) के अनुसार, 2019 में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 366 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई थी, जो वर्ष 2018 से लगभग 1.7 प्रतिशत बढ़ चुकी थी। वैश्विक अंतरिक्ष व्यवसाय का लगभग 75 प्रतिशत भाग वाणिज्यिक उपग्रह उद्योग है। प्रौद्योगिकी संबंधी नवीनताएं और बढ़ती मांग, उच्च बैंडविड्थ क्षमता, थ्रूपुटस्पीड, बेहतर ऑप्टिकल, रडार और थर्मल इमेजिंग की आवश्यकता को प्रबल बना देती है। पीडब्ल्यूसी का अनुमान है कि भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मान 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जोकि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग 2 प्रतिशत है।

अध्याय एक नज़र में

- भारत का सेवा क्षेत्र कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के लिए अनिवार्य लॉकडाउन के दौरान एक महत्वपूर्ण नुकसान का साक्ष्य रहा है। इसकी संपर्क-गहनता प्रकृति के कारण, इस क्षेत्र में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के दौरान करीबन 16 प्रतिशत का संकुचन आया है।
- मार्च 2020 में जैसे ही पहला लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, एयर पैसेंजर परिवहन, रेल फ्रेट ट्राफिक, बंदरगाह ट्राफिक, विदेशी पर्यटक आगमन, और विदेशी विनियम इन सभी में तेजी से संकुचन आया है। हालांकि, अब इनमें तीव्र सुधार के संकेत दिख रहे हैं।
- वैश्विक रूप से देखे जा रहे इन विधनों के बावजूद, भारत के सेवा क्षेत्र के एफ.डी.आई. के अंतर्वाह में अप्रैल-सितम्बर 2020 के दौरान दर वर्ष 23.6 बिलियन यू.एस. डॉलर के 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2020-21 कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार का साक्ष्य रहा है। आई.टी.-बी.पी.ओ. सेक्टर से टेलीकॉम संबंधित विनियमों को हटाकर ई. कॉमर्स के लिए उपभोक्ता संरक्षण विनियमों की शुरुआत की गई थी।
- बंदरगाहों के शिपिंग टर्न अराउंड समय को 2010-11 में 4.67 दिनों से 2019-20 में 2.62 दिन तक लगभग आधा कर दिया गया। अंकटाड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वैश्विक तौर पर जहाज का मध्य टर्न अराउंड समय 0.97 है; जो यह सुझाव प्रस्तुत करता है कि भारत के पास बंदरगाहों की दक्षता में और भी सुधार करने की संभावा है।

- कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय स्टार्ट-अप परितंत्र में काफी विकास हुआ है। भारत गत वर्ष युनिकॉर्न सूची में 12 स्टार्ट-अप्स की रिकॉर्ड संख्या के साथ 38 युनिकॉर्न्स का आवास स्थान है।
- गत छह दशकों में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में चार घातांक तरीके से वृद्धि हुई है। भारत ने 2019-20 में अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों में लगभग 1.8 बिलियन यू.एस. डॉलर खर्च किया है। हालांकि, यह देश अब भी इस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों जैसे कि यू.एस.ए. चीन और रूस से पिछड़ा हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष परितंत्र निजी खिलाड़ियों को नियोजित करने और नवोन्मेषणों व निवेश को आकर्षित करने के लिए कई नीतिगत सुधार कर रहा है।